The Statesman 20 February, 2017

# Insurance penetration may cross 4% this year: Report

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 19 February

Insurance penetration in India is expected to cross the four per cent mark by the end of this year amid proliferation of insurance schemes, says a report.

"The insurance penetration has started its northward journey is evident from the fact that it has increased from 3.3 per cent in 2014 to 3.44 per cent in 2015 on the back of various insurance schemes launched by the government," said the Assocham report.

During the first decade of the sector's liberalisation, there has been a consistent rise in insurance penetration from 2.71 per cent in 2001 to 5.20 per cent in 2009.

However, since then the level of penetration has been volatile and remained below the peak. It declined from 3.9 to 3.3 per cent in 2014 due to certain regulatory changes and unfavourable market conditions.

India's insurance penetration as a whole in 2015 was 3.4 per cent, against the world average of 6.2 per cent.

"Despite the gentle rise in insurance penetration, which is percentage of insurance premium with reference to the gross domestic product (GDP), it is still far below the global average," the report observed.

"The number of lives covered under health insurance policies during financial year 2015-16 was 36 crore which is approximately 30 per cent of India's total population. The number has seen an increase every subsequent year as 28.80 crore people had the policy in the previous fiscal," it pointed out.

As part of social security initiatives, the government has launched low-premium insurance schemes both life and non-life in 2015, it said, adding that last year, it introduced crop insurance.

With the objective of providing insurance cover to all, the government launched Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJBY) in 2015.

Rashtriya Sahara

20 February, 2017

# खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मिलेंगे 90 लाख रोजगार

▶ इस उद्योग में वर्ष 2024 तक 33 अरब डालर का होगा निवेश ▶ उद्योग मंडल एसोचैम की रिपोर्ट में जारी किया गया अनुमान

■ नई दिल्ली।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में वर्ष 2024 तक 33 अरब डालर के निवेश तथा करीब 90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उद्योग संगठन एसोचैम तथा बाजार अध्ययन एवं निवेश सलाह कंपनी ग्रांट थॉर्टन द्वारा यहां जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति निर्माताओं ने कृषि कार्य छोड़कर विनिर्माण की ओर बढ़ रहे श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में ही है। वर्ष 2024 तक इसमें 90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है जिसमें आठ लाख सीधी नौकरियां होंगी जबकि 82 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के साधन मिलेंगे।

इस समय देश का खाद्य प्रसंस्करण कारोबार 121 से 130 अरब डालर के बीच है। खेती लायक जमीन के मामले में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। हम दूध, दलहन, गन्ना और चाय के सबसे बड़े तथा गेहूं, चावल, फलों और सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। लेकिन, इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद यहां

प्रसंस्करण काफी कम होता है। कुछ उत्पादों में दो फीसद से लेकर कुछ उत्पादों में 35 फीसद तक ही प्रसंस्करण हो पाता है। केला, अमरूद, अदरक, पपीता आदि के उत्पादन में हम दुनिया के शीर्ष देशों में है। हालांकि इनका भी प्रसंस्करण कम होता है।

एसोचैम का कहना है कि वर्ष 2015 में देश के खाद्य एवं खुदरा बाजार का आकार 258 अरब डालर था जिसके वर्ष 2020 तक बढ़कर 482 अरब डालर पर पहुंच जाने की उम्मीद है। वैश्विकरण तथा सीमा पार बढ़ते व्यापार के साथ यहां हर साल 46 करोड़ टन खाद्य पदार्थों का व्यापार किया जाता है जिसकी कुल कीमत करीब तीन अरब डालर है। देश के कुल निर्यात में पिछले साल 12 फीसद हिस्सेदारी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की थी तथा वर्ष 2011 से 2015 के बीच इसकी सालाना वृद्धि दर 23.3 फीसद रही। इसलिए इस क्षेत्र में अभी काफी अवसर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र का योगदान 42 फीसद है। बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की मौजूदगी यह दिखाती है कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की बड़ी संभावना है। हालांकि, प्राथमिक प्रसंस्करण की तुलना में द्वितीयक प्रसंस्करण में संगठित क्षेत्र की उपस्थिति ज्यादा है।

देश के उपभोक्ता अपने कुल व्यय का 31 फीसद खाने-पीने के सामान तथा किराना सामान पर खर्च करते हैं जो अमेरिका (नौ फीसद) तथा चीन (25 फीसद) की तुलना में काफी ज्यादा है। खाद्य तथा किराना सामान देश के खुदरा कारोबार में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं। ■ वार्ता

**मनचाही**

- ■ आठ लाख लोगों को मिलेगा सीधे रोजगार
- ■ करीब 80 लाख लोगों को परोक्ष रूप से मिलेंगे रोजगार के अवसर
- ■ देश के कुल निर्यात में 12 फीसद का है इस खाद्य प्रसंस्करण का योगदान
- ■ इस समय 130 अरब डालर का है देश में खाद्य प्रसंस्करण का कारोबार

ASSOCHAM IN THE NEWS

**Dainik Jagran** 20 February, 2017

# खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र देगा 90 लाख नौकरियां

फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीयों के रोजगार का बड़ा जरिया बनेगा। औद्योगिक संगठन एसोचैम और वैश्विक अकाउंटिंग फर्म ग्रैंड थॉर्टन ने संयुक्त रूप से एक अध्ययन जारी किया है। यह बताता है कि 2024 तक इस क्षेत्र में 90 लाख नौकरियां पैदा होंगी। वहीं प्रत्येक राज्य में इससे सीधे तौर पर 8 हजार और अप्रत्यक्ष रूप से 80 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

## तैयार खाद्य में बदलना है प्रसंस्करण

अनाज, फल, सब्जियों और दूध को विभिन्न प्रक्रियों के जरिए तैयार खाद्य में बदलना ही प्रसंस्करण कहलाता है। आटा, बिस्कुट, जैम, जैली मक्खन जैसे खाद्य इसी प्रक्रिया से तैयार होते हैं। अनाज की पैकेजिंग भी खाद्य प्रंसस्करण में आती है।

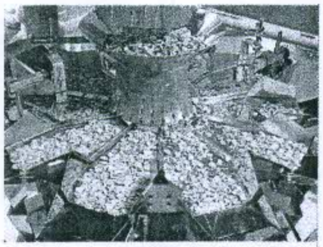

## बड़ा हो रहा बाजार

- लोगों की आय में इजाफे से बढ़ रही है प्रोसेस किए हुए खाद्य पदार्थों की मांग
- शहरीकरण, एकल परिवार के चलते 2020 तक दोगुनी होगी इनकी खपत
- 15.9 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के साथ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है भारत
- चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ उत्पादक है भारत
- इसके बावजूद विभिन्न खाद्य सामग्रियों की केवल 35 फीसद हो रही है प्रोसेसिंग
- इस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने से प्रोसेस्ड फूड उत्पादन में होगी बढ़ोतरी
- बड़े स्तर पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर

**130** अरब डॉलर
देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आकार

**2-35%**
विभिन्न खाद्यों की इतनी ही हो पाती है प्रोसेसिंग

**12%**
पिछले कुछ वर्षों में प्रोसेस्ड फूड के देश से निर्यात का आंकड़ा

**23.3%**
इनके निर्यात में होने वाला सालाना इजाफा

**482** अरब डॉलर
2020 तक देश के खाद्य रिटेल बाजार का संभावित आकार

**60%**
देश के रिटेल क्षेत्र में खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी

Amar Ujala

20 February, 2017

# खाद्य प्रसंस्करण में निकल सकती हैं 90 लाख नौकरियां

खास खबर

## 130 अरब डॉलर का जल्द ही हो जाएगा भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्ष 2024 तक 33 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है और इस कारण इस अवधि तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 90 लाख रोजगार निकल सकते हैं। यह खुलासा एसोचैम-ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट में किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में रोजगार सृजन करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीति निर्धारकों ने श्रमिकों को खेती से विनिर्माण की ओर ले जाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान की है। वर्ष 2024 तक देश के विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 8,000 प्रत्यक्ष नौकरियां तो 80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार निकलेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जल्द ही 121 अरब डॉलर से 130 अरब डॉलर का हो जाएगा। रिपोर्ट के अध्ययन के मुताबिक, भारत दूध, दाल, गन्ने व चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही गेहूं, चावल, फल व सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इतनी बड़ी मात्रा में फल-सब्जी के उत्पादन के बावजूद भारत में विभिन्न उत्पादों की प्रसंस्करण दर 2-35 फीसदी है। भारत केला, अमरूद, अदरक, पपीता जैसे फलों के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है, जबकि भारत की प्रसंस्करण क्षमता सीमित है। इस प्रकार की स्थिति में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफी अधिक अवसर हैं। अध्ययन के मुताबिक, भारतीय खुदरा बाजार का आकार वर्ष 2020 तक 482 अरब डॉलर तक का हो जाएगा। वर्ष 2015 में खुदरा बाजार का आकार 258 अरब डॉलर का था। भारत से घरेलू व वैश्विक स्तर पर सालाना 46 करोड़ टन खाद्य पदार्थों का कारोबार होता है, जो मूल्य के हिसाब से 3 अरब डॉलर का है।